डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 जून, 2022, डिस्पेच दिनांक 1 जून, 2022

| वर्ष 66 | अंक 01 | भोपाल | 1 जून, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

गुजरात पद्धति पर होगी मध्यप्रदेश में प्राकृतिक खेती : मुख्यमंत्री

मंत्रालय में हुई नव-गठित बोर्ड की पहली बैठक

सफल प्रयोग देखने अध्ययन यात्रा पर जाएंगे मध्यप्रदेश के जन-प्रतिनिधि और किसान

हरियाणा और गुजरात के बाद प्राकृतिक कृषि बोर्ड बनाने वाला राज्य है मध्यप्रदेश

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि की प्राचीन पद्धति प्राकृतिक कृषि, भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। इस तरह की कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता। इस नाते पर्यावरण के लिए अनुकूल और देसी गाय के गोबर और गौमूत्र पर आधारित प्राकृतिक कृषि को मध्यप्रदेश में बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नवगठित प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड की मंत्रालय में हुई पहली बैठक में कहा कि मध्यप्रदेश में प्राकृतिक कृषि से संबंधित कार्यों को गुजरात पैटर्न पर संचालित करें। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत गत 13 अप्रैल को भोपाल आए थे और उन्होंने प्राकृतिक कृषि के महत्व के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी सार्वजनिक कार्यक्रम एवं कार्यशाला में दी थी। श्री आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक कृषि का सफल प्रयोग भी किया है। उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार संपूर्ण कार्य-योजना लागू की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक कृषि विकास योजना के प्रथम चरण के कार्यों को प्रारंभ किया जाए। हरियाणा और गुजरात राज्यों के बाद मध्यप्रदेश ने प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन कर लिया है। मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं पशुपालन श्री जे.एन. कंसोटिया एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेंद्र सिंह और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों का प्राकृतिक कृषि के लिए पूर्व में पंजीयन के लिए आहवान किया गया था। इसके बाद किसानों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिली। अब तक प्रदेश में करीब 25 हजार कृषकों ने प्राकृतिक कृषि में रुचि प्रदर्शित की है और इसके लिए पंजीयन भी करवा लिया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कृषि विश्वविद्यालयों के स्तर पर प्राकृतिक कृषि को अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नर्मदा नदी के दोनों ओर 5 किलोमीटर क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए प्राकृतिक कृषि का कार्य प्रदेश के 5710 ग्रामों में प्रारंभ होगा। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में 100 ग्राम चयनित करने का लक्ष्य है। प्रेरक द्वारा 20-20 ग्राम चिन्हित कर दायित्व निभाया जाएगा। सर्वाधिक ग्राम इंदौर जिले में रहेंगे।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

प्राकृतिक खेती का अधिकतम प्रसार जरूरी : एसीएस श्री केसरी

रिजेनरेटिव कृषि स्थापित करने एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

भोपाल : प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये किसानों को प्रोत्साहित कराना जरूरी है। अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजीत केसरी ने मंत्रालय में रिजनरेटिव कृषि को स्थापित करने के लिये किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और आईडीएच (इण्डिया) के बीच हुए एमओयू हस्ताक्षर के दौरान यह बात कही। संचालक कृषि श्रीमती प्रीति मैथिल और आईडीएच की ऑपरेशनल हेड जसमीर ढींगरा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

एसीएस श्री केसरी ने बताया कि एमओयू का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि एवं किसानों को प्राकृतिक खेती के लिये प्रोत्साहित करना है। प्राकृतिक खेती से वर्तमान में किये जा रहे रसायनों के उपयोग को नियंत्रित किया जा सकेगा। एमओयू अनुसार कार्यक्रम के लिए मार्च 2026 तक की अवधि निर्धारित की गयी है। एमओयू के मुख्य घटक प्रोडक्शन, संरक्षण और समावेश हैं। प्रोडक्शन में उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधिकरण, कृषकों के लिये जलवायु अनुकूल कृषि पर जोर दिया जायेगा। संरक्षण में मृदा स्वास्थ्य, जल-संरक्षण, प्रबंधन, जैव-विविधता एवं ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए काम किया जायेगा। समावेश में आय में वृद्धि एवं आजीविका विविधिकरण, उत्पाद के लिये मूल्य श्रृंखला निर्माण एवं बाजार तक पहुँच और महिलाओं एवं समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिले नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से नाबार्ड, मध्यप्रदेश के मुख्य महाप्रबंधक श्री निरूपम मेहरोत्रा ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान को श्री मेहरोत्रा ने प्रदेश ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सशक्त बनाने में नाबार्ड द्वारा दिये जा रहे सहयोग की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को श्री मेहरोत्रा ने प्रदेश में ग्रामवासियों के आर्थिक उन्नयन के लिए डिजिटल और वित्तीय साक्षरता अभियान, रूरल मार्ट, आजीविका उद्यम विकास कार्यक्रम, प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण और एग्री इनक्यूबेशन सेंटर ग्वालियर के माध्यम से कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के बारे में बताया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नाबार्ड द्वारा ग्रामीण और सहकारी बैंकों को दिए जा रहे सहयोग की भी मुख्य महाप्रबंधक से जानकारी ली।

श्रमिकों के संकट में सहारा देने वाली अद्भुत योजना है संबल : मुख्यमंत्री श्री चौहान

गरीबों को बाधाओं से पार कराकर सीधी मदद पहुँचाएगी संबल योजना

सिंगल क्लिक से संबल हितग्राहियों के खाते में हुए 573 करोड़ 39 लाख रूपए अंतरित

तेंदूपत्ता संग्राहकों को भी मिलेगा योजना का फायदा

एमपी ऑनलाइन, नागरिक सुविधा और लोक सेवा केंद्रों से ऑनलाईन लिये जायेंगे आवेदन

आवेदन मिलने के बाद हितग्राही को लाभ मिलने तक होगी ट्रेकिंग व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया संबल 2.0 पोर्टल का शुभारंभ

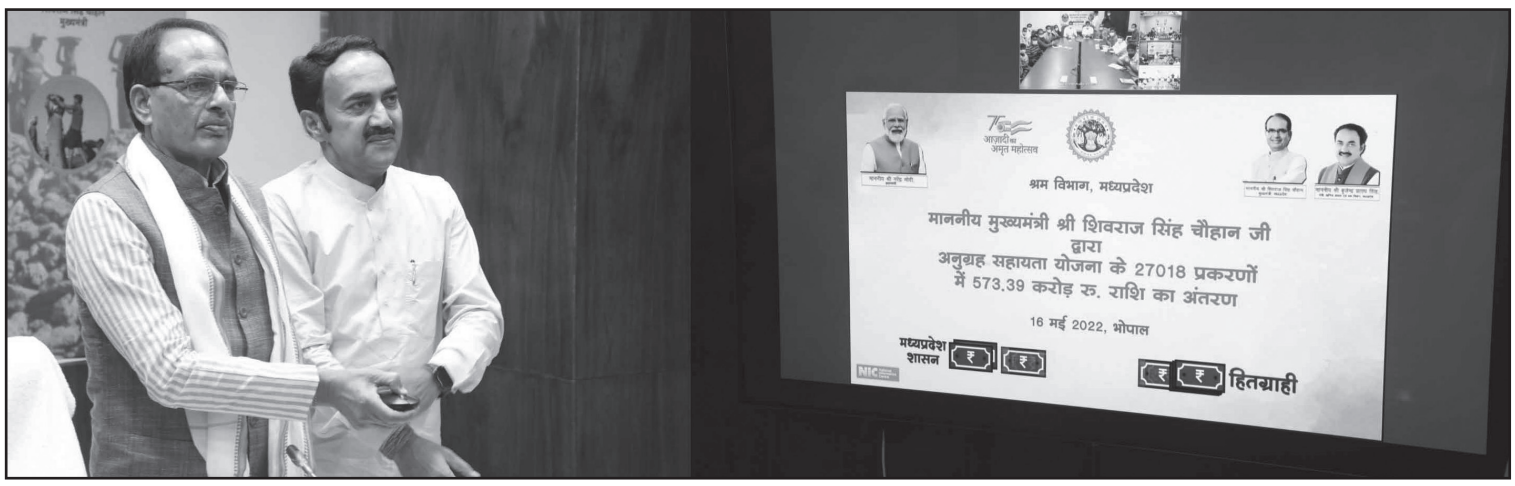

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संबल-2.0 योजना का लाभ सभी श्रमिकों के परिवार को मिलेगा। यह योजना हितग्राहियों को पूरे जीवन में संकट और आर्थिक आवश्यकता की स्थितियों में लाभान्वित करने वाली अद्भुत योजना है। योजना गरीबों का संबल है। चाहे आकस्मिक दुर्घटना हो या बीमारी के समय आर्थिक सहारा देने की बात हो या फिर हितग्राही परिवार के किसी परिजन की मृत्यु का मामला हो, संबल योजना श्रमिकों को बाधाओं से पार कराकर मदद पहुँचाने के लिए बनाई गई थी। वर्ष 2018 में इस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ था। पूर्व सरकार ने योजना के क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया और बंद कर दिया। हितग्राहियों के नाम सूचियों से काट दिए गए। अनेक गरीब इसके लाभ से वंचित रह गए। अब हमने इसे पूरे जोर-शोर से लागू करने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से सिंगल क्लिक द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के श्रमिक परिवारों को संबल योजना में राशि का अंतरण कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राही श्रमिक परिवारों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से संबल योजना को नए सिरे से लागू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगल क्लिक द्वारा संबल योजना के 25 हजार 982 श्रमिक परिवारों को 551 करोड़ 16 लाख तथा 1036 निर्माण श्रमिकों को 22 करोड़ 23 लाख रूपए, इस तरह कुल 27 हजार 18 प्रकरणों में 573 करोड़ 39 लाख रूपये हितग्राहियों के खातों में अंतरित किए।

नए हितग्राहियों को जोड़ने की व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने संबल योजना को अधिक हितग्राहीमूलक बनाते हुए नए स्वरूप का निर्धारण किया है। साथ ही अब योजना में हितग्राहियों को जोड़ने की कार्यवाही भी प्रारंभ हो जाएगी। नवीन पंजीयन प्रक्रिया में प्रदेश के लाखों तेंदूपत्ता संग्राहकों को भी असंगठित श्रमिक के रूप में शामिल किया गया है। योजना के लिए आवेदन एमपी ऑनलाइन, नागरिक सुविधा और लोक सेवा केंद्रों से किए जाने की सुविधा की गई है। संबल-2.0 योजना में वे श्रमिक भी नए सिरे से आवेदन कर सकेंगे, जिन्हें पूर्व में अपात्र घोषित कर दिया गया था। आवेदन प्राप्त होने के बाद अब प्रत्येक स्तर पर ट्रेकिंग से हितग्राही को लाभ दिलवाने का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।

मृत्यु और अपंगता की स्थिति में मिलता है आर्थिक सहारा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संबल 2.0 योजना में यह भी प्रावधान है कि हितग्राही आवेदन निरस्त होने पर अपील कर सकेगा। असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिक भाइयों को अनुग्रह सहायता योजना में दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर परिवार को 4 लाख रूपए की राशि दी जाती है। सामान्य दशा में मृत्यु होने पर भी 2 लाख रूपए प्रदान किए जाते हैं। यही नहीं स्थाई अपंगता पर 2 लाख रूपए, आंशिक अपंगता पर एक लाख रूपए प्रदान किए जाते हैं। अंतिम संस्कार सहायता के रूप में 5 हजार रूपए की राशि दी जाती है। योजना के पात्र वे सब श्रमिक हैं, जिन्हें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी आदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता है। हितग्राही के परिवार के पास एक हेक्टेयर से कम कृषि भूमि होने, शासकीय सेवा में न होने और आयकर दाता न होने पर पात्रता प्राप्त होती है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रेरणा से मध्यप्रदेश में श्रमिकों को पूरी सहायता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए। उनकी प्रेरणा से मध्यप्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सहायता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम देखते हैं कि आज छोटा-मोटा कृषि कार्य करने वाले मुश्किल से पेट भर पाते हैं। हमारे छोटे-छोटे सब्जी बेचने वाले विक्रेता, मजदूरी करने वाले, तेंदूपत्ता संग्राहक, चाय की दुकान चलाने वाले तथा अन्य वस्तुएँ बेचने वाले संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी सदस्य इस योजना में शामिल होंगे। सभी पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ा जाएगा। संकट के समय सरकार श्रमिकों के साथ खड़ी है। मध्यप्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण पर भी प्राथमिकता से कार्य कर रही है। आज जो पोर्टल लाँच किया गया है, वह भी योजना को गति प्रदान करेगा। हितग्राही अब लोक सेवा केंद्रों से आवेदन दे सकते हैं। उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, सभी के नाम योजना की हितग्राही सूची में जोड़े जाएंगे।

इस मानवीय और अद्भुत योजना का अधिक से अधिक प्रचार कर पहुँचाये जरूरतमंदों को सहायता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। ग्राम पंचायत और अन्य संस्थाओं में इस अभिनव और अद्भुत योजना की सूचना पहुँचाई जा रही है। सरकार विभिन्न समाचार-पत्रों और प्रसार माध्यम से भी इसका प्रचार करेगी। यह एक मानवीय योजना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जो महिलाएँ प्रसव के समय पर्याप्त आराम नहीं कर पाती, उन्हें योजना में 16 हजार रूपए की राशि दी जाएगी। प्रसव के पूर्व दी जाने वाली सहायता पहले 4 हजार और प्रसव के पश्चात दी जाने वाली सहायता राशि 12 हजार रूपये है। यह योजना बहनों के लिए प्रसूति के कष्ट दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बुद्धि का निर्धनता से कोई संबंध नहीं है। अभावग्रस्त परिवारों में भी प्रतिभावान बच्चे होते हैं। श्रमिकों के बच्चों को स्कूल जाने के लिए साइकिल प्रदान की जाएगी और उच्च शिक्षा के लिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सहायता दी जाएगी। अपने लाभकारी प्रावधानों की वजह से संबल योजना सभी के साथ न्याय करेगी। विद्यार्थियों के बढ़ते कदम नहीं रूकेंगे। उन्हें सक्षम बनाकर राष्ट्र सेवा के लिए तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कैंसर जैसे रोगों के उपचार की व्यवस्था भी योजना में है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों तक पहुँचाने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारियों और जन-प्रतिनिधियों द्वारा प्रचार का आग्रह किया। इससे जरूरतमंद लोगों को मदद पहुँचाने के प्रयास सार्थक होंगे।

प्रारंभ में श्रम एवं खनिज साधन मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबल योजना को वर्ष 2018 में लागू किया था। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के विभिन्न चरण में इस योजना का लाभ मिलता है। प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या 13 लाख 45 हजार है। इनके लिए 19 योजनाएँ संचालित हैं। गत वित्त वर्ष में एक लाख 81 हजार प्रकरणों में 557 करोड़ 45 लाख की राशि प्रदान की गई। दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणों में 535 करोड़, सामान्य मृत्यु के प्रकरणों में 21 करोड़, अपंगता के प्रकरणों में 3 करोड़ 4 लाख रूपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। अंत्येष्टि सहायता के रूप में 2 लाख से अधिक प्रकरणों में 105 करोड़ रूपए की राशि दी जा चुकी है। आज श्रमिकों के हित में संबल-2 योजना का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान की पहल से तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में क्रिस्प संस्था द्वारा कौशल प्रशिक्षण का लाभ भी श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा। मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है, जहाँ चार श्रमोदय विद्यालय संचालित हैं। प्रवासी श्रमिकों को भी कोरोना काल में पूरी सहायता दी गई। आज भी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने करीब 600 करोड़ रूपए की राशि का अंतरण श्रमिकों के खाते में किया है। मध्यप्रदेश सरकार श्रमिकों का अधिकाधिक ध्यान रखती है।

संबल -2.0 की प्रमुख विशेषताएँ

जहाँ संबल 1.0 योजना में पंजीयन के लिए 2018 में प्रारंभ की गई व्यवस्था वर्ष 2019 में बंद कर दी गई थी, उसे अब पुन: प्रारंभ किया गया है। अक्टूबर 2018 के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र असंगठित श्रमिक और तेंदूपत्ता संग्राहक का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। पूर्व में जिन्हें पंजीयन कार्ड नहीं दिए गए थे, अब उन्हें पंजीयन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। पहले योजना में पंजीयन के समय पात्रता संबंधी बिन्दुओं पर स्व-घोषणा थी। अब पंजीयन के समय पात्रता संबंधी बिन्दुओं की जाँच का प्रावधान किया गया है। आवेदक परिवार के अन्य सदस्य और आसपास के व्यक्तियों के कथन और फोटो को आधार बनाया गया है। पहले हितग्राहियों के हाथों के सत्यापन की व्यवस्था नहीं थी, जो अब कर दी गई है। इसी तरह आधार ई-केवाईसी और मृतक के आधार विवरण लेने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। अब वास्तविक हितग्राही का चिन्हांकन और आधार जानकारी का अपडेशन हो सकेगा। एक व्यक्ति एक खाता संबंधी व्यवस्था पोर्टल से रहेगी। पंजीयन और हित लाभ के आवेदन भौतिक रूप से जनपद एवं निकाय में जमा होते थे, जिन्हें ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से की गई है। एसएमएस से ट्रेकिंग करना भी संभव होगा।

राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न फसलों के उत्पादन में म.प्र. अग्रणी : मुख्यमंत्री श्री चौहान

11 विविध कृषि जलवायु क्षेत्र होने से प्रदेश में कृषि के विविधीकरण की अपार संभावना

टमाटर उत्पादन के लिए प्रदेश के 11 जिलों का चयन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव को किया संबोधित

टोमेटो सॉस और टमाटर प्र-संस्करण इकाई स्थापित करने युवाओं को वितरित किए चेक

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की "एक जिला-एक उत्पाद" योजना में 11 जिलों को विशेष रूप से टमाटर उत्पादन के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के किसान की आय दोगुना करने के लक्ष्य को हम कृषि के विविधीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा कृषि वैज्ञानिकों, प्र-संस्करणकर्ताओं, निर्यातकों से सलाह लेकर इस दिशा में गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। टमाटर के साथ फल-फूल, सब्जी, मसाला, औषधीय और सुगंधित फसलों की खेती और उनके प्र-संस्करण एवं व्यापार की अपार संभावनाएँ हैं। इस क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान होटल आमेर ग्रीन्स में उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग द्वारा नीदरलैंड ऐंबेसी के सहयोग से हुए इंटरनेशनल टोमेटो कान्क्लेव–2022 को निवास कार्यालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। कॉन्क्लेव में उद्यानिकी मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा, नीदरलैंड के राजदूत श्री मार्टन वान डेन बर्ग, चेयनमेन एम.पी.एग्रो श्री एंदल सिंह कंसाना, कृषि काउंसलर श्री मिशेल वान एर्कल, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति श्री कोटेश्वर राव और कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण श्री जे.एन. कंसोटिया मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के विस्तार के लिए केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं के साथ फल, पौध-रोपण, व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती को प्रोत्साहन, उद्यानिकी के विकास के लिए यंत्रीकरण को प्रोत्साहन, मसाला क्षेत्र विस्तार, खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के विकास, मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्र-संस्करण और उद्यानिकी फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज अधो-संरचना विकास के लिए योजनाएँ चलाई जा रही हैं। प्रदेश में कृषि उत्पादन की लागत घटाने, कृषक को उपज का उचित मूल्य दिलाने, बेहतर बाजार व्यवस्था स्थापित करने और प्राकृतिक आपदा में कृषक को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराकर खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रभावी कार्य जारी हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से समाज स्वास्थ्यगत समस्याएँ झेल रहा है। अब प्राकृतिक कृषि को अपनाने और उसे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से अपने खेत के एक भाग में प्राकृतिक खेती से उपज लेने का आहवान किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 11 विविध कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न फसलों के उत्पादन में मध्यप्रदेश अग्रणी स्थान पर है। संतरा और धनिया बीज उत्पादन में प्रदेश, देश में प्रथम है। साथ ही अमरूद, टमाटर, प्याज, फूलगोभी, हरी मिर्च, मटर, लहसुन, नींबू आदि के उत्पादन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं किसान हैं और अमरूद, अनार, आम की पैदावार लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि उनके द्वारा 9 एकड़ क्षेत्र में 766 टन टमाटर की पैदावार ली गई। किसानों के आर्थिक संबल के लिए कृषि का विविधीकरण आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंटरनेशनल टोमेटो कान्क्लेव-2022 प्रदेश में टमाटर फसल और उसके निर्यात, भंडारण, प्र-संस्करण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। राज्य सरकार विशेषज्ञों द्वारा विकसित रणनीति का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने "एक जिला-एक उत्पाद" में प्रधानमंत्री सूक्ष्म, खाद्य, उद्योग उन्नयन योजना में टोमेटो सॉस इकाई की स्थापना के लिए सिंगरौली के श्री लवकुश प्रजापति को 10 लाख 80 हजार रूपए, दमोह के श्री नारायण सिंह को 11 लाख 46 हजार रूपए और दमोह के ही श्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर को टमाटर प्र-संस्करण के लिए 26 लाख 60 हजार रूपए का चेक प्रदान किया।

उत्पादन से लेकर बाजार तक की बनाना होगी व्यवस्था : केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर

केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिये फसलों के उत्पादन से लेकर बाजार तक की व्यवस्था बनानी होगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश उद्यानिकी और प्राकृतिक खेती में बहुत अग्रणी है। मध्यप्रदेश ने सिंचाई और कृषि उत्पादन में बहुत उन्नति की है। खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में भी प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव वर्तमान समय की आवश्यकता है।

उद्यानिकी के हर क्षेत्र में हो रहा विस्तार : राज्य मंत्री श्री कुशवाह

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह ने टोमेटो कॉन्क्लेव-2022 के उद्घाटन-सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में उद्यानिकी के हर क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। आत्म-निर्भर किसान और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव-2022 करने का निर्णय सितम्बर-2021 में लिया गया था। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के विकास की संभावनाएँ मौजूद हैं। प्रदेश के 11 जिलों में किसानों ने टमाटर की खेती को प्रमुखता से अपनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए इन जिलों में "एक जिला-एक उत्पाद" में टमाटर को लिया गया है। मध्यप्रदेश की पहचान उद्यानिकी हब के रूप में होगी। कॉन्क्लेव से प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा। उद्यानिकी राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि कॉनक्लेव में विषय-विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों को अमल में लायेंगे।

किसानों को नई तकनीक से परिचित कराना जरूरी : राजदूत श्री मार्टिन

नीदरलैण्ड के राजदूत श्री मार्टिन बेन डेनवर्ग ने कहा कि किसानों को फसलों के उत्पादन से जुड़ी नई तकनीक का ज्ञान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ नीदरलैण्ड की पिछले 75 वर्षों से क्लोज फ्रेण्डशिप है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल टोमेटो कॉनक्लेव-2022 से टमाटर उत्पादन में किसानों को लाभ मिलेगा।

प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से कहा कि किसानों को सरल और सहज भाषा में उनकी आवश्यकताओं के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी दें। उद्यानिकी आयुक्त श्री ई. रमेश कुमार ने कॉन्क्लेव की रूपरेखा से अवगत कराया। कॉन्क्लेव किंगडम ऑफ द नीदरलैण्ड, नीदरलैण्ड की संस्था सॉलीडरीडाड और राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग ने किया।

प्राकृतिक खेती में नम्बर-1 है मध्यप्रदेश : कृषि मंत्री श्री पटेल

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में नये-नये कीर्तिमान गढ़ रहा है। आज प्रदेश प्राकृतिक/जैविक खेती में देश में नम्बर-1 है। प्रदेश में 16.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक/जैविक खेती की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में प्राकृतिक/जैविक खेती से 14.02 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया है। प्रदेश ने पिछले वित्त वर्ष में 2683 करोड़ रूपये मूल्य के 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक के जैविक उत्पाद निर्यात किये हैं।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया है कि प्रदेश में प्राकृतिक कृषि के रकबे को अधिक से अधिक बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने देशी गाय पालने पर प्रति गाय 900 रूपये का अनुदान देने का भी निर्णय लिया है। किसानों से आह्वान किया गया है कि वे खेती के कुल रकबे में से कुछ रकबे में प्राकृतिक खेती करें।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने बेहतर स्वास्थ्य के लिये किसानों से प्राकृतिक कृषि करने और उपभोक्ताओं से जैविक उत्पादों का प्रयोग करने का आह्वान किया है।

बिना लिए दिए समय-सीमा में लोगों के काम हों, यही सुशासन है-मुख्यमंत्री श्री चौहान

ऐसी व्यवस्था स्थापित करें, जिससे लोगों को शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ें, फोन पर या ऑनलाइन काम हों और लोग राहत महसूस करें

शाजापुर की प्याज के सीधे निर्यात के लिए स्थानीय लोगों को दें प्रशिक्षण

शाजापुर के हर स्कूल, कॉलेज में गठित हो बिजली बचत के लिए विद्यार्थियों का क्लब

जल्दी ट्रांसफार्मर जलने के कारणों की जाँच की जाए और ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोगों के काम बिना लिए दिए समय-सीमा में हों, यही सुशासन है। सीएम हेल्पलाइन, गवर्नेंस वन-डे, सीएम ऑनलाइन इसे सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास हैं। सीएम हेल्पलाइन को सुशासन का प्रभावी साधन बनाना है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में लोग अपने कामों के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर क्यों काटें? ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है, जिससे फोन या ऑनलाइन से ही लोगों के काम हों और लोग राहत महसूस करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान शाजापुर जिले की विकास गतिविधियों, जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। प्रातः 6:30 पर निवास कार्यालय से समीक्षा में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार वर्चुअली सम्मिलित हुए। शाजापुर कलेक्टर श्री दिनेश जैन सहित जिले के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शाजापुर से वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे और पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना को भी वर्चुअली जोड़ कर आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के समाधान में सर्वोच्च 5 जिलों में सम्मिलित होने के लिए शाजापुर जिले की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शाजापुर जिला सुशासन में आदर्श बनने का प्रयास करे। विकास कार्यों, जन-कल्याणकारी योजनाओं तथा थाना स्तर पर भ्रष्टाचार करने वालों की जानकारी तत्काल प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर सूचना तंत्र विकसित किया जाए। जिन अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या कार्य में विलंब की शिकायतें हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। ईमानदारी और लगन से कार्य करने वालों को राज्य शासन की ओर से संरक्षण और उन्हें प्रोत्साहित करने की व्यवस्था भी स्थापित करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले में हुए नवाचार, पेयजल आपूर्ति की स्थिति, राशन वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों, स्वास्थ्य व्यवस्था, आँगनवाड़ियों के संचालन, अमृत सरोवर योजना और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक जिला-एक उत्पाद में जारी गतिविधियों, महिला स्व-सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आँगनवाड़ियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद और संस्कारों के केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसे शाजापुर जिला टॉस्क के रूप में लें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शुजालपुर चिकित्सालय की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शाजापुर जिले से ही ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया गया था। अतः बिजली बचाने के लिए शाजापुर जिला पूरे प्रदेश में आदर्श स्थापित करे। कलेक्टर शाजापुर ने जानकारी दी कि जिले के सभी स्कूल, कॉलेजों में बिजली बचत के लिए विद्यार्थियों के क्लब गठित किए गए हैं। शासकीय कार्यालयों में भी अनावश्यक बिजली नहीं जलाने को लेकर अधिकारियों-कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बिजली बचाने के प्रयासों में निरंतरता जरूरी है, इस बात का ध्यान रखा जाए कि अभियान में शिथिलता नहीं आए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले में ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर जल्दी जल जाने की शिकायतें आने पर ट्रांसफार्मर जल्दी जलने के कारणों की प्रदेश स्तर पर समीक्षा के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ट्रांसफार्मर बदलने में भ्रष्टाचार की शिकायतें गंभीर है, इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जाए। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा स्वयं की एनएबीएल लैब में ट्रांसफार्मर परीक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे समस्या के निराकरण में मदद मिलेगी। साथ ही दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उन्हें सेवा से पृथक किया जा रहा है।

समीक्षा में बताया गया कि राजस्व समस्याओं के निराकरण के लिए जिले में नवाचार करते हुए गुलाना तहसील के 80 गाँवों को चार भागों में बाँटा गया। डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में राजस्व अमले की टीमों द्वारा गाँव-गाँव केम्प कर राजस्व संबंधी सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इस नवाचार में 3 माह में 40 हजार प्रकरण निराकृत किए गए है। नवाचार का वकीलों, पत्रकारों और महाविद्यालयों के व्याख्याताओं द्वारा थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी कराया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शाजापुर जिले के प्याज के निर्यात की प्रक्रिया का स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिलवाकर शाजापुर से सीधे अन्य देशों में निर्यात की व्यवस्था विकसित की जाए। उल्लेखनीय है कि एक जिला-एक उत्पाद में शाजापुर जिले में प्याज को लिया गया है। जिले में होने वाला प्याज देश के विभिन्न स्थानों तक जाने के साथ इसका निर्यात कोलकाता के एजेंटों के माध्यम से बांग्लादेश तक किया जाता है।

मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में शीर्ष निकाय और टास्कफोर्स गठित

भोपाल : राज्य शासन ने मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में शीर्ष निकाय तथा टास्कफोर्स का गठन किया है, जो राज्य में प्राकृतिक कृषि के प्रसार को बढ़ाने और सतत मार्गदर्शन के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करेगा।

मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के शीर्ष निकाय में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष है। सदस्य के रूप में वित्त मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, सहकारिता मंत्री, उद्यानिकी मंत्री, मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव उद्यानिकी, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास और मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित 4 विषय विशेषज्ञ प्राकृतिक और प्राकृतिक कृषि के उन्नत कृषक शामिल है। प्रमुख सचिव किसान कल्याण, कृषि विकास एवं म.प्र. प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के राज्य परियोजना संचालक सदस्य सचिव हैं।

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स में मुख्य सचिव अध्यक्ष है। कार्यकारी संचालक मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड सदस्य सचिव है।

सदस्य के रूप में कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव मप्र शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं राज्य परियोजना संचालक प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास, प्रमुख सचिव उद्यानिकी, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कुलपति जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, कुलपति राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यायल ग्वालियर, कुलपति पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, संचालक उद्यानिकी, संचालक पशुपालन और प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड शामिल है।

हर किसान की कृषि भूमि को मिलेगा सिंचाई के लिये जल- मुख्यमंत्री श्री चौहान

बीना नदी परियोजना से घर-घर पहुँचाया जाएगा पेयजल

हर गरीब को आवासीय भूमि का पट्टा देकर मालिक बनाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने किया 500 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेगमगंज में किसी भी किसान की जमीन बिना सिंचाई के नहीं रहेगी और बीना नदी परियोजना से हर घर में जल पहुँचाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गुरुवार को रायसेन जिले के बेगमगंज में लगभग 500 करोड़ रूपये की लागत के हर घर जल, सिंचाई और अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भगवान ने हवा, पानी और जमीन सबके लिए बनाई है। हर गरीब को आवास की जमीन का पट्टा देकर जमीन मालिक बनाना हमारा संकल्प है। भू-अधिकार योजना में 36 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। हम गुंडों, माफियाओं से अवैध रूप से हथियाई जमीन जब्त करेंगे और गरीबों को बाटेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है। शनिवार को प्रदेश के साढ़े 7 करोड़ परिवारों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि डाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने आँगनवाड़ी को सशक्त बनाने के लिए चलाई गई मुहिम का उल्लेख करते हुए समाज के सभी वर्गों का आहवान किया कि बच्चों को पोषित करने की जवाबदारी समाज ले।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनता के कल्याण और प्रदेश के विकास में पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। यह हमारा संकल्प है कि प्रदेश में कोई भी गरीब पक्के मकान के बिना नहीं रहेगा। सबको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों का विकास और कल्याण हमारी प्राथमिकता है। बेटी की शादी, बीमारी का इलाज, युवाओं को रोजगार, बच्चों की शिक्षा, सब मामा करवाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के कार्यो को तपस्या बताते हुए कहा कि वे जन-कल्याण के लिए हर पल परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। इससे पहले सुश्री भारती ने मुख्यमंत्री श्री चौहान की सरकार की सराहना की और कहा कि श्री शिवराज जी सेवा के रूप में तपस्या कर रहे है। कार्यक्रम को मंत्री और पूर्व मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री रमाकांत भार्गव और क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री श्री रामपाल सिंह ने भी सम्बोधित किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा गोरखा से सिमरिया तक 77 लाख 99 हजार रुपए की लागत के 2.692 किमी लंबे मार्ग, 94 लाख 26 हजार रुपए की लागत के नकातरा से पटी तक 2.65 किमी लंबे मार्ग, टी – 1 (भोपाल विदिशा रोड) से नरोदा तक 35 लाख 49 हजार रुपए की लागत के एक किमी लंबे मार्ग, ग्रेवल मार्ग 151 से केसली तक 83 लाख 44 हजार रुपए लागत के 2.88 किमी मार्ग, टी-5 से चौका तक 39 लाख 96 हजार रुपए लागत के 0.65 किमी मार्ग, रिमझा से पाला बम्होरी तक 150 लाख 09 हजार रुपए की लागत के 5.36 किमी मार्ग, टिकारी बम्होरी से नारायणपुर तक 102 लाख 14 हजार रुपए लागत के 3.66 किमी मार्ग, टी-1 से पथाकरैया पथाकलां तक 93 लाख रुपए लागत के 3 किमी लंबे मार्ग, परासिया से नगपुरा तक 108 लाख रुपए लागत के 3.50 किमी मार्ग, सिलवानी रोड से साजखेड़ा तक 35 लाख 26 हजार रुपए लागत के 1.10 किमी मार्ग का, मवई से कंजेला तक 41 लाख 33 हजार रुपए लागत के 1.20 किमी, चांदबड़ से बेरखेड़ी तक 85 लाख रुपए लागत से 1.80 किमी, खरबई से मेंडोरी तक 35 लाख 41 हजार रूपए लागत के 1.10 किमी, मानपुर रोड से पाछीपुरा तक 68 लाख 62 हजार लागत के 1.95 किमी, विनायकपुर से मुंधलाबेर तक 85 लाख 57 हजार रुपए लागत के एक किमी, बदगवाँ मुजाफता से तिनसाई तक 93 लाख 70 हजार रुपए लागत के 3.25 किमी मार्ग का शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री ने टेकापार खुर्द लघु सिंचाई योजना अनुमानित लागत 2311 लाख 36 हजार रुपए प्रस्तावित सिचाई क्षमता 725 और 1415 लाख 17 हजार रुपए लागत की बेरखेड़ी जोरावर लघु सिंचाई योजना प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 420 हेक्टेयर का शिलान्यास किया। गोपाई से चैनपुर तक 47 लाख 43 हजार रुपए लागत के 10 मीटर सूपान पुलिया निर्माण, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेगमगंज के 9.957 करोड़ रुपए लागत से निर्मित भवन और बेगमगंज बस स्टेंड पर 86 लाख रुपए लागत की विद्युत पोल स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण किया। ग्राम साईखेड़ा में 212 लाख 11 हजार रुपए लागत के रेट्रोफिटिंग नल-जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया। इनके अतिरिक्त अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया गया।

लाड़ली लक्ष्मियों ने प्यारे मामा मुख्यमंत्री श्री चौहान को लिखा पत्र

कन्या पूजन के समय लाड़ली लक्ष्मी बालिकाओं ने अपने प्यारे मामा मुख्यमंत्री श्री चौहान को पत्र लिखकर दिया। एक बालिका ने कहा कि - "मामा जी आपको धन्यवाद, आप के कारण मैं लाडली लक्ष्मी बनी और मुझे छठवीं कक्षा में छात्रवृत्ति मिल रही है।" मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी बालिकाओं को आशीर्वाद दिया और आगे खूब पढ़ाई करने को कहा।

जल जीवन मिशन में 609 करोड़ की जल-प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत
मिशन कार्यों में मध्यप्रदेश देश में पाँचवे स्थान पर

भोपाल : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने कहा है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्य पूरी गति से चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन से जल पहुँचाने के लिए जल-प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण होते ही जलप्रदाय प्रारंभ किया जा रहा है। प्रगतिरत योजनाओं का नियमित मौका मुआयना कर कार्य की गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। राज्य मंत्री श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिशन में हो रहे कार्यों की समीक्षा की जाती है, जिससे ग्रामीण आबादी को यथाशीघ्र उनके घर पर ही पेयजल सुविधा का लाभ दिया जा सके। राज्य मंत्री श्री यादव ने बताया कि मिशन में प्राप्त जल-प्रदाय योजनाओं के प्रस्ताव पर शासन स्तर से स्वीकृति दिये जाने की त्वरित कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 608 करोड़ 55 लाख 87 हजार रूपये लागत की जल-प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है, जिनमें नवीन और रेट्रोफिटिंग योजनाएँ शामिल हैं।

जल जीवन मिशन में प्रदेश के 49 लाख 80 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल मुहैया करवाया जा चुका है। जल परियोजनाओं का संचालन और संधारण ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा किया जा रहा है। मिशन में ग्रामीण क्षेत्र में संचालित स्कूल और आँगनवाड़ी में भी नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के 70 हजार 206 स्कूल और 40 हजार 803 आँगनवाड़ी केन्द्र में जल पहुँचाया जा चुका है, जो लक्षित संख्या का लगभग 60 प्रतिशत है।

मिशन में जल प्रदाय योजनाओं को पूरा कर 4 हजार 484 ग्रामों के शत-प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन से जल की सुविधा दी जा चुकी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम प्रदेश में विभिन्न जल-संरचनाओं पर निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे शत-प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक जल पहुँचाना संभव हो सके। प्रदेश में ग्रामीण आबादी के आकलन के अनुसार एक करोड़ 22 लाख ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है, इनमें 40.73 प्रतिशत से ऊपर लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। प्रदेश के 35 हजार 641 ग्राम के हर घर में नल से जल प्रदाय करने के लिए निरंतर कार्य जारी है। इनमें 3765 ग्राम की जल-प्रदाय योजनाओं की 90 प्रतिशत, 2157 ग्राम की 80, 1748 ग्राम की 70 और 27 हजार 868 ग्राम की प्रगति 60 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है।

मिशन कार्यों में मध्यप्रदेश देश में पाँचवे स्थान पर

जल जीवन मिशन में देश के सभी राज्यों ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने के लिये अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मिशन में 20 लाख से अधिक लक्ष्य वाले 10 राज्यों में अब तक प्राप्त उपलब्धि के आधार पर मध्यप्रदेश पाँचवे स्थान पर है। मिशन में मध्यप्रदेश ने जहाँ 40.73 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति कर ली है, वहीं असम छटवें, वेस्ट बंगाल सातवें, राजस्थान आठवें, छत्तीसगढ़ नवें और उत्तरप्रदेश दसवें स्थान पर है।

जून माह में बोई जाने वाली फसलें और किये जाने वाले कृषि कार्य

किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माह के अनुसार फसलों की बुवाई और कृषि कार्य करने चाहिए। साथ ही फसल की बुवाई के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए ताकि बंपर पैदावार प्राप्त हो सके। इसके लिए किसानों को प्रत्येक माह में बोई जाने वाली फसलों और उनकी देखरेख की जानकारी होना बेदह जरूरी है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम जून माह में बोई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ उनकी अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों से भी आपको अवगत करा रहे हैं ताकि आप अपने क्षेत्र के अनुकूल रहने वाली उन्नत किस्मों का चयन करके उत्पादन को बढ़ा सके।

धान की नर्सरी डालें

यदि किसान भाई मई के अंतिम सप्ताह में धान की नर्सरी नहीं डाल पाएं हो तो वे जून के प्रथम पखवाड़े तक यह काम पूरा कर सकते हैं। वहीं सुगंधित प्रजातियों की नर्सरी जून के तीसरे सप्ताह में डालनी चाहिए।

- धान की मध्यम और देर से पकने वाली प्रजातियां अच्छी मानी गई हैं। इसमें धान की स्वर्णा, पंत-10, सरजू-52, नरेन्द्र-359, जबकि टा.-3, पूसा बासमती-1, हरियाणा बासमती सुगंधित तथा पंत संकर धान-1 व नरेन्द्र संकर धान-2 प्रमुख उन्नत संकर किस्में हैं।
- धान की महीन किस्मों की प्रति हेक्टेयर बीज दर 30 किग्रा, मध्यम के लिए 35 किग्रा, मोटे धान हेतु 40 किग्रा तथा ऊसर भूमि के लिए 60 किग्रा पर्याप्त होता है, जबकि संकर किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर 20 किग्रा बीज की आवश्यकता होती है।
- यदि नर्सरी में खैरा रोग दिखाई दे तो 10 वर्ग मीटर क्षेत्र में 20 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम जिकं सल्फटे प्रति लीटर पानी में घोलकर छिडक़ाव करना चाहिए।

25 जून तक पूरी कर लें मक्का की बुवाई

- यदि आप मक्का की बुवाई करना चाहते हैं तो इसकी बुवाई 25 जून तक पूरी कर लेनी चाहिए। यदि सिंचाई की सुविधा हो तो इसकी बुवाई का कार्य 15 जून तक भी पूरा किया जा सकता है।
- मक्का की उन्नत किस्मों में शक्तिमान-1, एच.क्यू.पी.एम.-1, संकुल मक्का की तरुण, नवीन, कंचन, श्वेता तथा जौनपुरी सफेद व मेरठ पीली देशी प्रजातियां अच्छी मानी जाती हैं।

जून के प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं अरहर की बुवाई

यदि सिंचाई की सुविधा हो तो अरहर की बुवाई जून माह के प्रथम सप्ताह में की जा सकती है। वहीं सिंचाई की सुविधा का अभाव होने पर इसकी बुवाई वर्षा प्रारंभ होने पर ही करनी चाहिए।

- अरहर की उन्नत किस्मों में प्रभात व यू.पी.ए.एस.-120 शीघ्र पकने वाली तथा बहार, नरेंद्र अरहर-1 व मालवीय अरहर-15 देर से पकने वाली अच्छी किस्में है।
- अरहर की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 12-15 किग्रा बीज पर्याप्त होता है। अरहर के बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के बाद ही बोना चाहिए।

पशु चारे के लिए करें ज्वार, लोबिया व चरी की बुवाई

पशुओं के लिए हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए इस माह आप ज्वार, लोबिया और चरी जैसी चारे वाली फसलों की बुवाई कर सकते हैं। बारिश न होने की दशा में पलेवा देकर बुवाई की जा सकती है।

जून माह में करें इन सब्जियों की खेती

जून माह में आप बैंगन, मिर्च, अगेती फूलगोभी की पौध लगा सकते हैं। भिंडी की बुवाई का भी ये उपयुक्त समय है। इसके अलावा लौकी, खीरा, चिकनी तोरी, आरा तोरी, करेला व टिंडा की बुवाई भी इस माह की जा सकती है। भिंडी की उन्नत किस्मों में परभनी क्रांति, आजाद भिंडी, अर्का अनामिका, वर्षा, उपहार, वी.आरओ.- 5, वी.आर.ओ.-6 व आई.आई.वी.आर.-10 भिंडी की अच्छी किस्में मानी जाती है।

जून माह में करें ये कृषि कार्य

- सूरजमुखी/उड़द/मूंग जायद में बोई गई सूरजमुखी व उड़द की कटाई मड़ाई का कार्य 20 जून तक आवश्यक रूप से पूरा कर लेना चाहिए।
- इसी के साथ ही मूंग की फलियों की तुड़ाई का कार्य भी समय समाप्त कर लें।
- गर्मी की जुताई व मेड़बंदी का काम बारिश से पहले पूरा कर लेना चाहिए, जिससे खेत बारिश का पानी सोख सके और खेत की मिट्टी बारिश में नहीं बह पाए।
- पिछले माह बोई गई बैंगन, टमाटर व मिर्च की फसलों में सिंचाई व आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई कार्य करें।

जून माह में किए जाने वाले बागवानी कार्य

- यदि आप नया बाग लगा रहे हैं तो इसके रोपण के लिए प्रति गड्ढा 30-40 किग्रा सड़ी गोबर की खाद, एक किग्रा नीम की खली तथा गड्ढे से निकली मिट्टी को मिलाकर भरें। इस बात का ध्यान रखें कि गड्ढे को जमीन से 15-20 सेमी. ऊंचाई तक भरा जाना चाहिए।
- केला की रोपाई के लिए यह उचित समय है। इसके रोपण के लिए तीन माह पुरानी, तलवारनुमा, स्वस्थ व रोगमुक्त पुत्ती का ही प्रयोग करें।
- आम में ग्राफ्टिंग का कार्य जून-जुलाई में करना काफी अच्छा रहता है, क्योंकि इस माह में बारिश का पानी हमेशा गुटी के उपर पड़ता रहता है। इससे अंकुरण सही रूप से होता है। इस मौसम में ऊपर से पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन गुटी व ग्राफ्टिंग में छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखना आवश्यक है। इनमें दो दिन पूर्व पौधे के पत्ते को हटा देना चाहिए और टहनियों की ठीक ढंग से चिराई करनी चाहिए ताकि उच्च गुणवत्ता वाली टहनी इसमें आसानी से समा सके। ध्यान रहे टहनियां तकरीबन वर्ष भर पुरानी होनी चाहिए। जिसमें अंकुरण निकल सके। अब इसके प्रवर्द्धन की बात करें तो जून व जुलाई माह में आम के पौधे को लगाया जाना उचित माना जाता है। आम की नई प्रजातियों में आम्रपाली व मल्लिका दो ऐसी किस्में है जिसमें प्रतिवर्ष फल लगते हैं।
- रजनीगंधा, देशी गुलाब एवं गेंदा के साथ उगे अनावश्यक पौधे जिन्हें खरपतवार कहते हैं उन्हें हटाने का कार्य करें ताकि सुगंधित पौधों का ठीक से विकास हो सके। इसके अलावा इन पौधों में आवश्यकतानुसार सिंचाई का कार्य भी करते रहें।
- रजनीगंधा की फसल से प्रति स्पाइक फूलों की संख्या व स्पाइक की लंबाई बढ़ाने के लिए जी.ए. (जिब्रेलिक एसिड) 50 मिग्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर पत्तों पर इसका छिडक़ाव करें। बेला तथा लिली में निराई-गुड़ाई का कार्य करें और आवश्यकतानुसार इसकी सिंचाई का कार्य करें।
- मेंथा की दूसरी कटाई जून माह के अंत तक पूरी कर लेनी चाहिए। बता दें कि मेंथा को पुदीना भी कहा जाता है। इससे पिपरमेंट और तेल तैयार किया जाता है। इसका उपयोग दवाइयां, सौंदर्य उत्पाद, टूथपेस्ट, पान मसाला संग कंफेक्शनरी उत्पादों में होता है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

गुजरात पद्धति पर होगी मध्यप्रदेश में प्राकृतिक खेती...

इंदौर जिले के 610 ग्रामों में प्राकृतिक कृषि की तैयारी है। कृषि विभाग से आत्मा (एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी) के जिला स्तरीय अमले का उपयोग प्राकृतिक कृषि के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अभी कुछ जिलों के कुछ ग्रामों में प्राकृतिक कृषि हो रही है। इनमें नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिले भी शामिल हैं। यहाँ हो रहे कार्य के अनुरूप अन्य ग्रामों तक प्राकृतिक कृषि का विस्तार करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण देने के लिए कार्य करने वाले प्रेरकों के लिए प्रशिक्षण शेड्यूल बनाएँ। आत्मा का स्टाफ इस कार्य में संलग्न करने संबंधी कार्रवाई भी पूर्ण की जाए।

10 लाख से अधिक ले चुके हैं प्रशिक्षण

भोपाल में शून्य बजट, प्राकृतिक कृषि पद्धति विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत के ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने के लिए प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्री और किसान शामिल हुए थे। यह कार्यशाला 13 अप्रैल को हुई थी। प्रदेश में कुल 10.65 लाख प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण का लाभ वर्चुअली प्राप्त किया था। इसके बाद 18 से 20 मई को गुजरात सरकार ने मास्टर ट्रेनर्स की सहायता से मध्यप्रदेश के 52 जिलों में प्रशिक्षण शिविर लगाकर करीब 3 हजार अधिकारियों और कृषि विभाग के मैदानी अमले एवं 6 हजार 247 कृषकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया। बताया गया कि वर्तमान में 7.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि के लिए किसान आगे आए हैं। प्रत्येक जिले में प्रेरक मास्टर्स ट्रेनर्स की भूमिका निभाएंगे। मध्यप्रदेश में आगामी रबी सीजन से प्राकृतिक कृषि का रकबा निर्धारित किया जाएगा और किसानों को इसके लिए प्रेरित किया जाएगा।

प्राकृतिक कृषि देखने जाएंगे मध्यप्रदेश के जन-प्रतिनिधि और किसान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के जन-प्रतिनिधि, कृषक और संबंधित अधिकारी हरियाणा एवं गुजरात का भ्रमण कर प्राकृतिक कृषि के सफल प्रयोगों को देखेंगे। इन राज्यों के अलावा भी कहीं प्राकृतिक खेती हो रही है तो उसकी अध्ययन यात्रा की जाएगी। श्री आचार्य देवव्रत के कार्य के परिणाम सबके सामने हैं। उनका अनुसरण करना ही बेहतर है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग प्राकृतिक कृषि के विकास में किया जाएगा। विशेषज्ञों की सेवाएँ लेने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

प्राकृतिक खेती का अधिकतम प्रसार जरूरी....

संचालक कृषि श्रीमती मैथिल ने बताया कि एमओयू में लॉड्स फाउंडेशन, डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. और आई.डी.एच. मध्यप्रदेश के 9 जिलों के एक लाख किसानों के साथ मिलकर तीन लाख हेक्टेयर भूमि में रिजनरेटिव कृषि को स्थापित करने का कार्य करेंगे। उत्पादों के बेहतर विपणन के लिये इसे बाजार से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जायेगा। छिन्दवाड़ा, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, धार, बड़वानी, खंड़वा, खरगोन और बुरहानपुर जिले में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन अलग-अलग सहयोगियों के साथ मिलकर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री श्री मोदी का माना आभार

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व स्तर पर उर्वरक की बढ़ती कीमतों के बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों के कल्याण के लिए बजट में एक लाख 5 हजार करोड़ रूपए की उर्वरक सब्सिडी के अलावा एक लाख 10 हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस निर्णय के लिए प्रदेश के किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना है।

पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित

भोपाल : आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।

गौरतलब है कि पंचायत निर्वाचन-2022 मतपत्र और मतपेटी के द्वारा करवाया जाएगा। पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होगा।

प्रदेश में साख जमा अनुपात को बढ़ाने का पूरा प्रयास करें बैंकर्स : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 का बैंकर्स तेजी से करें क्रियान्वयन

महिला स्व-सहायता समूहों को आगे बढ़ाने अधिकाधिक स्वीकृत करें ऋण

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की प्रगति बढ़ाने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 182 वीं बैठक हुई

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैंकर्स प्रदेश में साख जमा अनुपात को बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। जनजातीय बहुल जिलों में बैंकों की शाखाएँ बढ़ाकर ऋण स्वीकृति पर अधिकाधिक ध्यान दें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास कार्यालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 182 वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं बैंकर्स मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में वार्षिक साख योजना 2022 -23 की पुस्तिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में ज्यादा से ज्यादा ऋण प्रकरण स्वीकृत कर हितग्राहियों को लाभान्वित करें। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना में स्वीकृत प्रकरणों का वितरण समय पर हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निजी क्षेत्र की बैंक

सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर पीएम स्व-निधि योजना के प्रकरण स्वीकृत करें। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में भी स्वीकृत प्रकरणों के मुताबिक वितरण की कार्यवाही हो। उन्होंने एचडीएफसी बैंक द्वारा कम लक्ष्य प्राप्त किए जाने पर और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना में कम प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तेजी से कार्य करें। वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर माह का लक्ष्य तय किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने केसीसी पशुपालन एवं मत्स्य-पालन की प्रगति बढ़ाने पर जोर दिया। किसानों की आय दोगुना करने और मत्स्य-पालकों की स्थिति ठीक करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है। इस पर गंभीरता से पूरा ध्यान देकर कार्य करें। स्व-रोजगार योजना में एनपीए का वसूली प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति बढ़ाई जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में बैंकर्स तेजी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप पर बहुत जोर दे रहे हैं। मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति का अच्छे ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित कर तेजी से आगे बढ़ायें। युवाओं को अधिकाधिक रोजगार दिलाएँ। बैठक में स्विफ्ट इंडिया ऑटोमेटेड ई- स्टाम्पिंग पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसका उपयोग शुरू कराने की बात कही।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें। मध्यप्रदेश विकासशील राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, इसलिए सीडी रेशियो पर गंभीरता से ध्यान दें। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाए। समूहों को आगे बढ़ाने के लिए अधिकाधिक ऋण स्वीकृत करें। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्गों के रोजगार सृजन पर ध्यान दें। प्रदेश में हर माह रोजगार दिवस मनाया जाएगा। हर माह का लक्ष्य निर्धारित कर रोजगार दिलायें। महत्वाकांक्षी योजनाओं के लक्ष्य पूरा कर बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करें। कमजोर वर्गों में उद्यमशीलता बढ़ाने के पूरे प्रयास करें। उन्होंने 30 मई को रोजगार दिवस आयोजित करने के निर्देश दिए।

अभियान चलाकर किसानों को प्राकृतिक खेती के लिये करें प्रेरित: कृषि मंत्री श्री पटेल

पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिले

भोपाल :किसान-कल्याण तथा कृषि विकास और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल ने छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर विभागीय समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है कि हर हाल में शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले। कोई भी हितग्राही लाभों से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भ्रमण के दौरान मैदानी निरीक्षण पर यदि लाभों से वंचित होने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में कृषि मंत्री श्री पटेल ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लिये अभियान चलाकर प्रोत्साहित करने को कहा है। विभिन्न विभागों की समीक्षा प्रभारी मंत्री द्वारा की गई।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने जिले में कृषि के कुल रकबे, उत्पादित फसलों के साथ

ही खाद-बीज और उर्वरक की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। कृषि मंत्री श्री पटेल ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कृषि में बढ़ते रासायनिक उपयोग के दुष्परिणाम से बचने के लिये जरूरी है कि प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें। उन्होंने इसके लिये प्रत्येक गाँव में शिविर आयोजित कर प्राकृतिक खेती के लाभों से अवगत कराने को कहा है। मंत्री श्री पटेल ने प्राकृतिक खेती के लिये किसानों को प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिये।

अभियान चलायें, घर-घर जाकर करें सर्वे

कृषि मंत्री श्री पटेल ने शासन की योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुँचाने के लिये घर-घर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सर्वे कर हितग्राहियों की पात्रता का परीक्षण करें और पात्रतानुसार उन्हें लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि योजनाओं का जरूरतमंद तक लाभ हर हाल में पहुँचे, इसमें किसी प्रकार गड़बड़ी न हो, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

गौ-शालाओं का करें बेहतर संचालन

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि सड़कों पर गौवंश दिखाई नहीं दे, इसके लिये जरूरी है कि गौ-पालन और गौ-शालाओं का संचालन बेहतर तरीके से किया जाये। गौ-शालाओं में पानी और भूसे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। गौ-पालन के लिये शासन द्वारा दी जा रही सहायता गौ-पालकों को उपलब्ध करायें।

जनपद पंचायत परासिया के नव-निर्मित भवन का किया लोकार्पण

कृषि मंत्री श्री पटेल ने छिंदवाड़ा के परासिया जनपद पंचायत के नव-निर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि 80 लाख रूपये की लागत से बनाये गये नव-निर्मित भवन में कार्य करने से निश्चित ही कर्मचारियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिसका लाभ सभी को मिलेगा। बेहतर वातावरण से परिणाम भी बेहतर प्राप्त होते हैं।

एफओआर उर्वरक प्रदाय योजना हेतु इन्वेन्टरी मैनेजमेंट कर्मचारी हेतु कार्य दायित्व निष्पादन विषय पर एक दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण

भोपाल। म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र. द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी संघ को सहकारी संस्थाओं में मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु कार्य सौंपा गया है। जिसके तहत संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन के मार्गदर्शन में इन्वेन्टरी मैनेजर को उनके जाबवर्क, बैंक एवं पैक्स के संबंध, पैक्स में एफओआर उर्वरक योजना में इन्वेन्टरी मैनेजमेंट कर्मचारी की भूमिका एवं उनकी पदस्थापना का उद्देश्य, एफओआर उर्वरक योजना के तहत इन्वेन्टरी मैनेजर द्वारा किया जाने वाला व्यवहारिक कार्य, कुशलतापूर्वक कार्य पर संस्थाओं को होने वाले लाभ एवं लापरवाही से होने वाली हानि,, एफओआर उर्वरक योजना के तहत तैयार पोर्टल का संचालन एवं इन्वेन्टरी मैनेजर द्वारा उनका उपयोग, ऑनलाइन पोर्टल का संचालन पर श्री के.टी. सज्जन, ए.जी.एम.,अपेक्स बैंक, सुश्री वर्षा चौहान, सामान्य सहायक, अपेक्स बैंक, श्री प्रदीप नीखरा,से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता, श्री विनय प्रकाश सिंह, सी.ई.ओ., सीसीबी, विदिशा, श्रीमति मंदिरा लोध , डी.डी.एम. आई.टी., विपणन संघ, श्रीमति मीनाक्षी बान कम्प्यूटर व्याख्याता, संघ द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के उपरांत संघ के श्री संजय सिंह, ओ.एस.डी, द्वारा प्रमाण पत्र वितरण किये गये। इस कार्यक्रम में श्री संतोष येडे, राज्य समन्वयक, श्री जी.पी.मांझी, प्राचार्य, श्री धनराज सैंदाणे, श्री विक्रम मुजुमदार, श्री विनोद कुशवाह का विशेष सहयोग रहा।

बैंक सायबर सुरक्षा पर कार्यशालाओं का आयोजन

इन्दौर। वर्तमान में सहकारी बैंक अपना सारा बैकिंग कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से कर रहे है। ऐसे में बैंक कार्य व्यवहार में सायबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुऐं म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा सायबर अपराध व सुरक्षा उपाय तथा कानूनी पहलू विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन, संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 12 मई 2022 को उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक मर्या., उज्जैन तथा दिनांक 20 मई 2022 को उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक मर्या., उज्जैन में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में सायबर अपराध क्या है, बैंक में सायबर सुरक्षा क्यो महत्वपूर्ण है, बैंक सायबर सुरक्षा के प्रकार व उपाय तथा आई. टी. एक्ट की जानकारी दी गई।

सभी प्रशिक्षार्थियों ने कार्यक्रम को वर्तमान समय के अनुसार बहुत उपयोगी बताया। प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यसामग्री भी वितरित की गई। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित

(म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम

Higher Diploma in Cooperative Management (HDCM)

माध्यम - ऑनलाईन

योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण अवधि - 20 सप्ताह ऑनलाईन आवेदन/

प्रवेश की अंतिम तिथि – 15 जून 2022

कुल फीस - 20200/-

ऑनलाइन आवेदन / प्रवेश हेतु राज्य संघ के

पोर्टल www.mpscuonline.in पर विजिट करें।

संपर्क :-

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित , भोपाल

ई- 8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल फोन : 0755-2926160 , 2926159

मो. 8770988938 , 9826876158

Website-www.mpscu.in, Web Portal-www.mpscuonline.in

Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र

किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006

फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053

Email - ctcindore@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र

हनुमान ताल जबलपुर, म.प्र पिन - 482001

फोन- 0761-2341338 मो. 9424782856 , 8827712378

Email - ctcjabalpur@gmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव

जिला छत्तरपुर, म.प्र. पिन – 471201

फोन- 07685-256344 मो. 9630661773

Email - ctcnowgong@gmail.com

भारत में सहकारिता आंदोलन को मजबूत किये जाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली द्वारा करवाया गया अध्ययन

भोपाल। केन्द्र सरकार द्वारा ''सहकार से समृद्धि'' के दृष्टिकोण को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिये नव गठित सहकारिता मंत्रालय दिल्ली द्वारा सम्पूर्ण भारत में राज्य सहकारी संघों एवं कनिष्ठ सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिये एवं सहकारिता की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने हेतु भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली (NCUI) को अधिकृत किया है। इस स्थिति की समस्त जानकारी हेतु एनसीयूआई नई दिल्ली द्वारा अध्ययन एग्रीकल्चर फायनेंस कार्पोरेशन इंडिया (AFC) के माध्यम से किया जा रहा है। जिसकी शोधकर्ता सुश्री सुरभी भारती, एवं सुश्री अंजली के माध्यम से जानकारियों का संकलन किया गया है। इसके तहत मध्यप्रदेश में म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल, के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन एवं श्री संजय सिंह, राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश के श्री संजय मोहन भटनागर, उपायुक्त, सहकारिता, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के श्री जी.पी. मांझी, प्राचार्य, श्री अरूण जोशी, सेवा निवृत्त प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर के श्री दिलीप मरमट तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के श्री व्ही.के. बर्वे द्वारा शिक्षा प्रशिक्षण, मानव संसाधन, अधोसंरचना, एवं आर्थिक तथा मध्यप्रदेश में सहकारिता का पूर्ण विकास न होने की स्थिति से अवगत कराया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।